



ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE  
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI  
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing

03 April, 2019

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson, AICC and Shri Shaktisinh Gohil, Spokesperson, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, एक प्रकार से हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो एक उदाहरण है, जिसकी व्यापकता ज्यादा है। अखिल भारतीय स्तर पर व्यापकता ज्यादा है और एक प्रकार से ये न्यायिक संदेश में है। न्यायपालिका का संदेश है, हर अफसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को, हर ऑब्जर्वर को, उनके लिए संदेश भी है और सबक भी है। मैं आपको इसके कुछ तथ्य दे दूँ और उसके बाद इसकी व्यापकता का जिक्र करूँगा। एक निर्णय कल आया है, उच्च न्यायालय गुजरात का, वहाँ के न्यायाधीश का, वहाँ के कोर्ट का, उससे ये सीधा मालूम पड़ा है कि किस प्रकार से वरिष्ठ कर्मचारी सरकार के, गुजरात काडर के और सेंटर के आईएएस, किस प्रकार से चुनाव के लिए जो समतल जमीन होनी अति आवश्यक है, लेवल प्लेयिंग फील्ड, उसको विकृत कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं ये मुद्दा विशेष रूप से सिद्धांत के रूप से, ये कोई ए और बी की बात नहीं है, इस केस की बात नहीं है, सिद्धांत रूप से ये अगर आप समतल जमीन नहीं रहने देते, चुनाव के वक्त, तो सीधा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव पर और स्वतंत्र, निष्पक्ष वोटिंग पर। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर जो दुष्प्रभाव होता है, वो हमारे कोर्ट कचहरियों ने दशकों से ये कहा है कि भारत के संविधान के मूल ढांचे पर दुष्प्रभाव है। It violates the basic structure of the Indian Constitution if you create a non-level playing field for electoral battle.

इस केस में जो कल निर्णित हुआ, ढोलका एसेंबली के विषय में है, जिसका चुनाव जैसा आप जानते हैं दिसंबर, 2017 में हुआ था और इसमें जो विजयी घोषित किए गए थे, वो चुदासमा साहब थे, जो उस वक्त राजस्व के मंत्री थे और आज कानून के मंत्री हैं। उनके चुनाव के विरुद्ध, चुनाव याचिका चल रही है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन जिस संदेश और सबक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंतर्गत एक आंतरिक ऑर्डर कल 2 अप्रैल को

आया है, अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत दो वरिष्ठ सरकारी अफसरों को और चुनाव आयोग को इस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पार्टी बनाया है, इस चुनाव याचिका में। वो हैं श्री जानी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और श्रीमती विनीता बोहरा, जो इस चुनाव में ऑब्जर्वर थीं, 2017 में। इसलिए बनाया पार्टी, जो बहुत कम किया जाता है, अपवाद होता है, रेयरली (rarely) किया जाता है, क्योंकि 5-6 मुद्दे उच्च न्यायालय ने अंकित किए हैं, जो पूरे देश में हर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, हर ऑब्जर्वर के लिए चुनाव आयोग की हर प्रक्रिया के लिए एक संदेश भी है और सबक भी। इसलिए कि चुदासमा साहब जीते थे 327 वोट से और जो पोस्टल बैलेट लगाए गए थे, वो खुद पोस्टल बैलेट 514 थे यानि जो मार्जन से ज्यादा पड़े थे और लगभग 429 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए थे। Rejection of postal Ballots were higher than the margin of victory. ये बातें अंकित करते हुए उच्च न्यायालय ने 5 या 6 मुद्दों को अंकित किया है, जो मैं आपके समक्ष संक्षेप में रख रहा हूँ।

पहला, जब पोस्टल बैलेट की संख्या, रिजेक्शन की संख्या या पोस्टल बैलेट की संख्या मार्जन से ज्यादा होती है, जो कि इस केस में थी, क्योंकि मार्जन था 327, रिजेक्शन था 439 और टोटल बैलेट थे 514, तो अनिवार्य है, बिना किसी के मांग किए, ऑटोमेटिकली कि रिवेरिफिकेशन हो, रिवेरिफिकेशन ऑटोमेटिक अनिवार्य है, अनुच्छेद या नियम 15.15.5.1 के अंदर। अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को बुलवाया गया, उनसे पूछा कि आपने ये नियमावली देखी है, उन्होंने कहा हां, देखी, इसमें ऐसा लिखा है, हाँ लिखा है, क्या आपको इसमें बिना किसी के मांगे, इस केस में मांगना चाहिए था, इस केस के अनुसार, कहा, हाँ मांगना चाहिए था। हमने कहा कि रिवेरिफिकेशन किया आपने, कहा नहीं किया। ये खुद रिटर्निंग ऑफिसर ने माना है, ये पहला मुद्दा है।

दूसरा नियम है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग होती है, बिना मांगे, क्योंकि इतना कम मार्जन है और पोस्टल वोट ज्यादा हैं। तो ये भी माना, ये एडमिशन है, ये जजमेंट की प्रतिलिपि मेरे सहयोगी आपको भेज देंगे, उसमें सवाल 278 और 279 में लिखा है, माना है कि ये हमने ना ऑटोमेटिक रिवेरिफिकेशन किया, ना रिकाउंटिंग की, तो ये दो मुद्दे रिकोर्ड किए हैं, कोट किए हैं उच्च न्यायालय ने। ये रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है।

तीसरा मुद्दा पूछा उनसे कि चूंकि ऐसे संदर्भ में जहाँ मार्जन बहुत कम होता है और पोस्टल वोट बहुत ज्यादा है, तो जब आप EVM की काउंटिंग के लास्ट लेवल पर पहुंचते हैं, उसके

एक राउंड पहले आपको रुकना चाहिए जब तक कि पोस्टल बैलेट रिकाउंट ना हो जाएं, ये एक नियम है। तीसरा नियम है, पूछा क्या किया आपने? उसने कहा नहीं किया मैंने। यानि EVM पहले काउंटिंग करते रहे, पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग और रिवेरिफिकेशन से पहले।

चौथा मुद्दा, एक और नियम पढ़ा, मैं नियम से नंबर नहीं दूंगा, इस आदेश में प्रकाशित है कि मोबाईल फोन अंदर कोई व्यक्ति नहीं ले जा सकता, गणना के समय सिवाए एक व्यक्ति के, ऑब्जर्वर को अलाउड है। जो प्रश्न पूछते हैं इस न्यायालय के निर्णय में कि क्या ये वीडियो देखी आपने, बड़ा मजाकिया संदर्भ है,

वीडियो में कौन दिख रहा है?, तो रिटर्निंग ऑफिसर जवाब देते हैं, मैं खुद हूं, क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं मैं फोन पर बात कर रहा हूं। ये इस नियम के अनुसार हैं, नहीं, ये इस नियम के अनुसार नहीं है। तो इसका उल्लंघन किया? चौथा जो उल्लंघन है यूज ऑफ मोबाईल।

पांचवा, आपने घोषणा कर दी जब पोस्टल बैलेट की, उससे पहले आपको फोर्म 20 पर लिखना पड़ता है कि पोस्टल बैलेट कितने हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, क्या आपने पहले लिखा? फोर्म 20 कहते हैं, भरा पहले, घोषणा पहले कर दी? उसने कहा हाँ, मैंने घोषणा पहले कर दी। तो इन पांच मुद्दों पर रिटर्निंग ऑफिसर के एडमिशन, स्वीकारिता रिकॉर्ड की है, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में।

छठा और आखिरी मुद्दा, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि कानून और नियम के अंदर ऑब्जर्वर क्यों भेजा जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है, विनीता बोहरा इसमें हैं, तो उनका काम होता है कि वो बैठ कर सर्टिफाई करें कि मेरे अनुसार मैंने सबकुछ देखा, निरीक्षण, परिक्षण किया और मेरे अनुसार सबकुछ नियम के अनुसार है और संतुलित है, फेयर है, निष्पक्ष है। ये सर्टिफिकेशन आपने कैसे कर दिया, इसलिए उनको भी पार्टी बनाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को भी और उनको भी, अंत में चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया गया है ताकि भविष्य में ये दोबारा ना हो, उसके लिए क्या करेक्टिव या क्या प्रिवेंट करने के लिए भविष्य में measure (कदम) लिए जाएं, उसके लिए चुनाव आयोग भी रहें, तो बेहतर होगा।

मैं अपनी बात का अंत करूंगा ये कहकर कि ये सिर्फ इस केस की बात नहीं है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संदेश है, विशेष रूप से अगले 5 या 6

हफ्तों के लिए। हर ऑफिसर को संदेश है, हर रिटर्निंग ऑफिसर, हर ऑब्जर्वर, हर उस कार्यकारी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग के लिए काम करता है कि आप बिना द्वेष के, बिना पक्षपात के, बिना झुकाव के, बिना भेदभाव के, बिना भय, बिना डरे किसी से अपना काम करें। ये बहुत जरूरी है। इस बात पर मत सोचिए कि सत्तारूढ़ कौन है, सत्तारूढ़ कौन नहीं है, कौन हमारे पर कृपादृष्टि रखेगा, कौन नहीं रखेगा, क्योंकि एक दृष्टि रखी हुई है आपके ऊपर हमेशा उच्च न्यायालय ने और उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय ने, चुनाव आयोग के साथ-साथ ये दृष्टि आपके ऊपर है, तो ये सबके लिए संदेश भी है, सबक भी है, चेतावनी भी है कि आप कृपा करके जो भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान मूल ढांचा है हमारे संविधान का, उसको विकृत ना होने दें, जबतक उस समतलता को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र, गणतंत्र का ढांचा हिल जाएगा, ढुल जाएगा।

**श्री शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि** सिंघवी साहब ने वैसे पूरी बात आपके सामने रखी है, लोकतंत्र में आखिर जनता तय करती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा। चुनाव आयोग जो भी अफसर को जिम्मेदारी देते हैं, वो अफसर ना इसका, ना उसका, न्यायिक तौर पर उसे काम करना होता है, ये सामान्यत होता आया है।

मोदी जी जनता के भरोसे चुनाव नहीं, अफसरों के भरोसे वो चुनाव कैसे जीतते हैं, उसका सीधा सबूत, जीता-जागता नमूना आपके सामने पेश हो रहा है। गुजरात हाईकोर्ट एक इलेक्शन पेटिशन सुन रहा है, इस इलेक्शन पेटिशन में जिसको जीता हुआ डिक्लेयर किया है, वो चुनाव लड़ रहे थे, तब कैबिनेट मिनिस्टर थे, फॉर रिवेन्यू, भूपेन्द्र सिंह चुदासमा। उसका फासला बहुत नेरो-नेरो होता जा रहा था, सेंटल इलेक्शन कमीशन को कानूनन क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी हैंडबुक सभी को दी जाती है कि ऐसा ही करना होगा। उसके सारे कानून 14 जगह पर कानून को उल्टा किया, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी को जिताना था। 327 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। आजतक आपने पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 1356 पोस्टल बैलेट आए थे, बैलेट माने उसी ऐसंबली में रहने वाला इंसान, अगर उसकी इयूटी चुनाव में कहीं लगी है तो खुद वोट देने नहीं आएगा, इसलिए उसको बैलेट मिलता है, उस बैलेट में वो जिसको भी वोट देना चाहता है, उसको वोट देता है, वो एनवलप पैक होता है, वो बैलेट होता है। ऐसे 1356 वोट थे, सारे गवर्मेंट इम्प्लोई हैं, पूरे देश में आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि सरकारी इम्प्लोई वोट करे और 1356 में से 429 रिजेक्ट हो गए। 327 से बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है और रिटर्निंग ऑफिसर 329 रिजेक्ट कर देता है।

कानून का प्रावधान है कि जब जीत और हार का फासला कोई भी उम्मीदवार हारे और जीते हुए का फासला कुल बैलेट जो आया है, उससे कम हो तो किसी को पूछे बिना, दो चीजें करनी हैं - कोई मांगे या ना मांगे रिकाउंटिंग करनी है, पहला। दूसरा, रिवेरिफिकेशन, मतलब अगर ये बीजेपी को वोट दिया है तो दिखाओ कि सही है और काउंटिंग किसमें कितना बैलेट है, ये जरूरी है, नियम है। इस नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है क्योंकि अगर रिकाउंटिंग होता, रिवेरिफिकेशन होता तो 429 वोट जिंदा हो जाते, जो कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी वाला 327 से जीता, वो हार जाता। आज तक जितनी देश में इलेक्शन पेटिशन हुई उसमें, जो ऑफिसर होते हैं, वो विटनेस होते हैं। हारने वाला पेटिशन लगाता है, जीतने वाले सामने वाले होते हैं, रिस्पॉंडेंट। ऑफिसर कभी रिस्पॉंडेंट नहीं होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कभी रिस्पॉंडेंट नहीं होता है, वो विटनेस होता है, रेयर और रेयर केस, पूरे देश के इतिहास में।

कोर्ट ने सारी चीजें लिखने के बाद लिखा कि- very serious glaring, कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, करप्ट प्रेक्टिस में जरूरी है कि रिस्पॉंडेंट बनाऊँ, सामने वाला बनाऊँ और उसको सामने वाला बनाते, किसको- एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं- श्री जानी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एक आईएएस ऑफिसर को भेजते हैं कि आपको देखना है कि सब ठीक हो रहा है और सर्टिफिकेट दो, फिर चुनाव की घोषणा होती है, वो राजस्थान कैडर की विनीता बोहरा, आईएएस ऑफिसर हैं, वो आई थी वहाँ पर, जिसने सर्टिफिकेट दिया है, उसको रिस्पॉंडेंट बनाया और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉंडेंट बनाया, क्योंकि घपला गंभीर है। पहले रिटर्निंग ऑफिसर को विटनेस बॉक्स में कोर्ट ने बुलाया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा आपको पढ़ने में लंबा लगेगा पर एक इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिज्म का मजा होता है, मैंने लॉ भी किया है और पत्रकारिता का डिप्लोमा कोर्स भी किया है तो हम इसे इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिज्म में मानते हैं। तो आप इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तो आगे के पेराग्राफ छोड़ दीजिए, पेज 8 ऑनवर्ड आप पढ़िए, पहले पेज का पेराग्राफ 1 और 2 है, थोड़ा फेक्ट मिलेगा आपको। उसके बाद पेज 8 से आगे पढ़िए, कोर्ट ने विटनेस बॉक्स में रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा है कि फासला दोनों के बीच का था, वो कितना था, उसने कहा 327, दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा कि कानून सो एंड सो, क्या कहता है - जब फासला पोस्टल बैलेट से कम हो तो रिकाउंटिंग और रिवेरिफिकेशन करना चाहिए। कोर्ट ने तीसरा सवाल पूछा कि कानून ये कहता है तो आपने किया रिकाउंटिंग, रिवेरिफिकेशन और जानी साहब जवाब देते हैं कि मैंने नहीं किया।

यहाँ तो हमारे उम्मीदवार ने लिख कर मांगा, मांगने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मांगा। कोर्ट ने पूछा, मांगा था रिकाउंटिंग, कहा मांगा था। फिर भी नहीं दिया, कहा नहीं दिया। आगे हैं, आप सब कभी काउंटिंग हॉल में जाते होंगे, आपने देखा होगा, मीडिया के लिए कमरा बनता है, आपके मोबाईल वहाँ रहते हैं, आप बात कर सकते हैं। काउंटिंग हॉल के अंदर जैसे ही एंटर हुए, किसी के हाथ में मोबाईल नहीं हो सकता, सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो सकता है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर हो सकता है, उनके पास कोर्ट ने वीडियो दिखाई, शॉट 7 जगह की, अलग-अलग समय की। सामने वाले का आरोप था कि ये मिनिस्टर को पूछते थे कि बापू आप तो हार रहे हैं, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा रास्ता ढूँढो। ये वीडियो दिखाते हैं और 7 जगह पर कहते हैं, क्या देख रहे हैं, बोले मैं हूँ, मोबाईल पर हूँ, बात कर रहा हूँ। कानून क्या कहता है - कानून कहता है कि मोबाईल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के अलावा कोई भी नहीं ले जा सकता, वो कानून कहता है।

तीसरी बात आती है, कोर्ट पूछता है कि कानून क्या है - बोले, जो भी राउंड होते हैं, एक विधानसभा में 200 से 250 बूथ होते हैं, एक बूथ पर 1,000 से 1,200 वोटर होते हैं, वो जो मशीन आई, उसके 15 टेबल लगते हैं और उन टेबल पर मशीन आती है, बूथों की, सब पर एक-एक बार हुआ, उसका एक राउंड। 15 से 16 राउंड होते हैं, यहाँ पर कानून ये कहता है कि आखिरी दो राउंड खत्म हों, उससे पहले बैलेट का काउंटिंग हो जानी चाहिए, लोजिकल है, क्योंकि फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कोर्ट पूछती है, जानी साहब को कि इसमें जजमेंट में लिखा है कि ये कानून है, बोले हां। आखिरी दो राउंड से पहले बैलेट की काउंटिंग हो जानी चाहिए, कहाँ हां, हो जानी चाहिए। फिर वीडियो दिखाते हैं, तो वीडियो में दिखता है कि वो काम नहीं किया और कानून का ऊल्टा किया, पहले EVM को खत्म कर दिया कि कितना फासला रहता है और कितने वोट रिजेक्ट करके बीजेपी को जिताना है, वो काम किया, वो भी कोर्ट ने लिखा है।

ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेरे पत्रकार मित्रों से विनती है कि कुछ लोगों ने मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन पर मिरर की एक स्टोरी है, उन्होंने कुछ हद तक इनवेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया, मैं चाहता हूँ कि आज आप वक्त निकाल कर इस पूरे जजमेंट को जरूर पढ़ें, सिंपल लैंग्वेज है, सब समझ सकें, ऐसी भाषा है और इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा Question mark आ गया। मैं मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इज्जत बनी रहे, इसके लिए भी इस बात को जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसको गंभीरता से लेंगे। जो दो ऑफिसर को कोर्ट ने पूरी तरह

से जिम्मेवार माना है, चुनाव आयोग तुरंत उनको सस्पेंड करे। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा बनाई बुक है, आने वाले चुनाव में हर जगह सख्ती से इसका पालन हो, कोई आईएस ऑफिसर, कोई रिटर्निंग ऑफिसर गड़बड़ी ना करे, वो चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। ये हमारी मांग है।

**श्री जानी, सुश्री विनीता बोहरा और चुनाव आयोग से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि दो तारीख अप्रैल को, कोर्ट ने बोला है कि अंततोगत्वा कि हमारी ट्राइल चल रही है लेकिन अभी इस आदेश द्वारा हम इन तीन लोगों को पार्टी बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, श्री जानी, सुश्री विनीता बोहरा और चुनाव आयोग, यानि रेस्पॉण्ड बना रहे हैं साथ ही साथ ये भी लिखा कि चुनाव आयोग को इसलिए बना रहे हैं कि भविष्य में ऐसी बात दोहराई नहीं जाए, कभी हो नहीं और बाकी दोनों एक प्रकार से कारण बताओ, क्या एक्शन लिया, क्यों किया, कैसे होना दिया इत्यादि, इत्यादि के लिए हम पार्टी बना रहे हैं।**

जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि ये बायलेटरल प्रोसीडिंग होती है, दो लोगों के बीच में, इसमें अफसरों के साथ बहुत-बहुत कम बार ऐसा होता है अपवाद होता है, जब बनाया जाता है, जबकि बहुत गंभीर मुद्दा होता है कोई ऐसी भ्रष्ट प्रैक्टिस होती है, जिसको भविष्य के लिए भी रोकना अति आवश्यक है तब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया की जाती है।

**चुनाव के समय मतदान केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि वहाँ पर वीडियोग्राफी का इस निर्णय में भी जिक्र किया गया है। नियम ऑलरेडी है, काउंटिंग वैरीफिकेशन, रीकाउंटिंग में वीडियोग्राफी अनिवार्य है लेकिन जहाँ तक आप ज्यादा बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं इसमें संभावना निश्चित है, इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो कि अनहोनी है या हो ही नहीं सकती इसीलिए ये चेतावनी है हम सबको कि इस चुनाव में ऐसा न हो। अभी दो दिन पहले मैंने खुद डेलीगेशन लीड किया है, जहाँ हमने लिखित प्रस्तुति की है, कि झारखंड में चार अफसर जो मुख्य पदों पर हैं चुनाव के लिए उनमें से तीन के विरुद्ध दफा 302 के चार्जज है तो हमने कहा कि विडंबना नहीं है इस देश को चुनाव के दौरान फिर वही अफसर मिलेगा लगाने के लिए, नियंत्रण परीक्षण करने के लिए जिसके विरुद्ध 302 के केस हैं, ये बात सही है कि वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन 302 के गंभीर अपराध के चार्जज हैं, और एक अफसर के विषय में हमने लिखकर दिया है, सबकुछ प्रमाण दिए हैं, एक अफसर के विषय में टेप रिकॉर्डिंग भी है वहाँ की झारखंड की पुलिस की जो बातचीत कैसे कर रहा है तो ये अंततोगत्वा ये बड़े बड़े सिद्धांत है, मानव अधिकार है, चुनाव आयोग है, समतल जमीन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है,**

लोकतंत्र, गणतंत्र हैं, ये बड़ी चीजें, छोटी चीजों पर निर्भर करती हैं, और वो छोटी चीजें हैं वहाँ पर जो लास्ट मैन ऑन दा स्पाॅट है जो जमीनी सच को देख रहा है वो मजबूत होना चाहिए तो दो बात हैं इस निर्णय में, एक तो ये है जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि आप ये न समझें कि गड़बड़ियाँ निकलती जाएंगी, ये न समझें कि पक्षपात छुपे रहेंगे, ये न समझें कि द्वेष की भावना से या झुकाव से आपको कोई सुरक्षित कर लेगा बाद में, क्योंकि जो आपकी सुरक्षा करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय है। तो ये उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है लेकिन एक प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, पूरे देश के लिए हर पार्लियामेंटरी क्षेत्र के लिए और अधिकारियों के लिए।

**On the question whether the Congress Party would request the Election Commission to not put Ms. Vinita Bohra on election duty again, Dr. Singhvi said-** we don't have to ask. There are strictures passed by the High Court judgment. The Election Commission must take automatic plea by way of rule in this country. If the Election Commission obligatorily takes account and note of judgment passed, Yes, the Election Commission is not only made a party, but a very strong observation have been made against two of its officers. I don't think anybody in this country can ignore these observations. They are in the nature of stricture and I have no doubt, that is the minimum, what you have said, will happen. Much more needs to be done for everything else by all other parties.

**On the reaction of the Congress Party on the biopic of Modi played by Shri Vivek Oberoi, Dr. Singhvi said-** I don't think I need to reply to people who are not in political realm directly. I think we have made more than submissions and what Shri Oberoi is saying, he should go and tell the Election Commission which has already issued notice to him on our representation. This is another example of absolute desperation. We have led three delegations to the Election Commission in one week. In one week, they have had a biopic, they have had a NaMo TV, and they are putting number of ads and NaMo things on Doordarshan, 'Chowkidar' campaign of Doordarshan. What this indicates apart from complete violation of every rule, apart from complete non-level playing field, it indicates a very-very high degree of desperation. Certain conviction of law can defeat so that you are clutching everywhere or some desperate way of convincing the public.

**On the question that Shri Jaitley has leveled against both Shri Rahul Gandhi and Ms. Priyanka Vadra Gandhi with regard to their farm houses what they call 'sweetheart' deal, Dr. Singhvi said-** Now, you can understand how desperate this party is and the increasing desperation in the Finance Minister's allegations. You know, when this allegation was first made, you were here sometimes back two years ago, and do you know that the word 'sweetheart' deal has it applied to what my friend just mentioned about 10,000% increase in Shri Shah's assets. At that time the



Finance Minister did not think of this word 'sweetheart'? A rental by a company, stale allegations, he remembers. He does not remember a 'sweetheart' deal when a man in India can multiply assets by 10,000 times.

**On the question of the reaction of the Congress Party on the tradition law, why is it that the Congress Party had sudden change of mind when Shri P. Chidambaram was the Home Minister, he has not charged everybody, Dr. Singhvi said-** the reason is that we have now realized how a provision which was largely ornamental on the statute book. It is capable of perverse misuse. Never in 70 years, and mark my word carefully, has any Government irrespective of political rivalry including Vajpayee Ji, BJP Government even fractionally used sedition in the number and degree as used by this Government. In five years, this Government has slapped the maximum number of sedition charges. If you draw cartoon of the Prime Minister, I can challenge you that you will be charged of sedition. Try it out. If you write about the Prime Minister, I can challenge you that you will need a Counsel for sedition. That has happened to so many people in Kerala and Karnataka. The sheer volume of misuse, lead us now to think. I agree with you that it could have been done earlier but earlier it was not being misused in this degree and frequency. We are now seeing it, we are experiencing it in five years and I think it is absolutely right that no other further future Government should be able to do like this again.

**Sd/-  
(Vineet Punia)  
Secretary  
Communication Deptt.  
AICC**

**IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD****R/ELECTION PETITION NO. 3 of 2018**

=====

ASHWINBHAI KAMSUBHAI RATHOD                      ...PETITIONER

Versus

BHAILALBHAI KALUBHAI PANDAV & ORS.                      ...RESPONDENTS

=====

Appearance :

MR P.C. KAVINA, SENIOR ADVOCATE with  
MR S.P. MAJMUDAR, ADVOCATE for the Petitioner

MR C.B. UPADHYAYA, ADVOCATE for the contesting Respondent No. 2

MR MEHUL S. SHAH, SENIOR ADVOCATE with  
MR JENIL M. SHAH, ADVOCATE for the Respondent No. 5

MR BHAGIRATH N. PATEL, ADVOCATE for the Respondent No. 12

=====

**CORAM: HONOURABLE MR.JUSTICE PARESH UPADHYAY**

**Date : 02/04/2019**

**ORAL ORDER (Exh.115)**

1. The subject matter of this Election Petition is the General Election to the Gujarat Legislative Assembly, 2017 for the '58 – Dholka Assembly Constituency'. In this Election Petition, the petitioner has made various grievances and has leveled serious allegations, including that of corrupt practice and breach of many of the mandatory instructions of the Election Commission of India, at various stages of the Election process, more particularly at the time of counting of votes. On the basis of the pleadings of the contesting parties, this Court had

framed 14 issues, reference to which is made herein after (Para : 4), for which trial is going on before this Court.

2. In this trial, the concerned Returning Officer is examined as a witness. His evidence is on record at Exh. 99. The recording of his evidence was concluded on the last date of hearing i.e. 15.03.2019. On the conclusion of the deposition of the Returning Officer, it has become necessary to join certain persons and authority as party respondents in this petition, which is ordered in the concluding part of this order (Paras : 14 and 15). The relevant facts and the circumstances, in which this is being done by this Court, are as under.

3.1 As noted above, challenge in this Election Petition is to the General Election to the Gujarat Legislative Assembly, 2017 for the '58 - Dholka Assembly Constituency'. Mr. Bhupendrasinh Manubha Chudasama (respondent No. 2) was the candidate set up by the Bharatiya Janta Party. Mr. Ashwinbhai Kamsubhai Rathod (the petitioner) was the candidate set up by the Indian National Congress Party. The said election was held on 14.12.2017. The counting and declaration of result took place on 18.12.2017. As per the said result, Mr. Bhupendrasinh Manubha Chudasama (respondent No. 2) is the returned candidate. The returned candidate, at the relevant time, was a Member of the Council of Ministers of the Government of Gujarat, with the portfolio of Revenue Department. At present also, he is a Member of the Council of Ministers of the Government of Gujarat, with the portfolio of the Departments of Education and Law & Justice.

3.2 As per the said Election Result, declared on 18.12.2017,

total number of valid votes cast in favour of the petitioner were 71203 votes. Total number of valid votes cast in favour of the returned candidate – the respondent no.2 were 71530 votes. The returned candidate thus got elected with the margin of 327 votes. The break-up of the total votes (through EVMs and Postal Ballots) is as under.

	Petitioner	Respondent No.2 (the returned candidate)	Difference of Votes in favour of the returned candidate
EVMs	70675	71189	514
Postal Ballots	528	341	-187
Total	71203	71530	327

3.3 Total votes received by the Returning Officer through postal ballot papers were 1356. Out of these total 1356 postal ballots, the Returning Officer rejected 429 votes. Thus, the number of rejected postal ballots (429 votes) were more than the winning margin (of 327 votes) of the returned candidate.

4. As noted above, the petitioner has made various grievances and has leveled serious allegations in this Election Petition, including that of corrupt practice and breach of many of the mandatory instructions of the Election Commission of India, at various stages of the Election, more particularly at the time of counting of votes. On the basis of the pleadings of the

contesting parties, this Court had, vide order dated 24.12.2018, framed 14 issues, to be tried in this petition. The said order was one of the many orders challenged by the returned candidate, before the Supreme Court of India by filing SLPs (Civil) Nos. 3075 to 3081 of 2019 and SLP (Civil) No. 3950 of 2019, which were dismissed as withdrawn by common order passed by the Supreme Court of India dated 11.02.2019. Those issues read as under.

1. Whether the petitioner proves that the procedure adopted for counting of votes for '58-Dholka Constituency' was against the orders of the Election Commission of India and was illegal?

2. Whether the petitioner proves that 429 postal ballot papers were illegally rejected at the time of counting of votes ?

3. Whether the petitioner proves that objection was raised by the petitioner, or his election agent, regarding alleged illegal rejection of postal ballot papers and / or non compliance of the orders of the Election Commission of India, at the time of counting of votes ?

4. Whether the petitioner proves that there are discrepancies in the figures of total votes polled, as reflected in the final result sheet published by the Returning

Officer, vis-a-vis the figures reflected in the Total Voters Turnout Report published by the District Election Officer ?

5. Whether the petitioner proves that there are discrepancies in the number of total votes shown to have been polled through EVMs at the polling stations, visa-vis the number of votes taken into consideration from those EVMs at the time of counting of votes ?

6. Whether the petitioner proves that the result of the election, in so far as it concerns the returned candidate (the respondent No.2) from '58-Dholka Constituency' for the Gujarat State Legislative Assembly Elections, held on 14.12.2017, has been materially affected by improper refusal / rejection of the votes ?

7. Whether the petitioner proves that the result of the election, in so far as it concerns the returned candidate (the respondent No.2) from '58-Dholka Constituency' for the Gujarat State Legislative Assembly Elections, held on 14.12.2017, has been materially affected by non-compliance with the provisions of the Representation of the People Act, and / or Rules or Orders made under the said Act ?

8. Whether the petitioner proves that any corrupt practice was committed under Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 during the election of '58-Dholka Constituency' held in December 2017 ?

9. Whether the petitioner proves that any corrupt practice was committed by the returned candidate (the respondent No.2) or his election agent or by any person with the consent of the respondent No.2 or his election agent during the election of '58-Dholka Constituency' held in December 2017 ?

10. Whether the petitioner proves that the election of the returned candidate (the respondent No.2) from '58-Dholka Constituency' for the Gujarat State Assembly Elections held on 14.12.2017, needs to be declared as void under Sec. 100(1)(d) (iii) of the Representation of People Act, 1951 ?

11. Whether the petitioner proves that the election of the returned candidate (the respondent No.2) from '58-Dholka Constituency' for the Gujarat State Assembly Elections held on 14.12.2017,

needs to be declared as void under Sec. 100(1)(d) (iv) of the Representation of People Act, 1951 ?

12. Whether the petitioner proves that the election of the returned candidate (the respondent No.2) from '58-Dholka Constituency' for the Gujarat State Assembly Elections held on 14.12.2017, needs to be declared as void under Sec.100(1)(b) of the Representation of People Act, 1951 ?

13. Whether the petitioner proves that he is entitled to be declared as duly elected candidate from '58-Dholka Constituency' for the Gujarat State Assembly Elections held on 14.12.2017 ?

14. What final order to be passed ?

5. The trial, qua the above quoted issues, is going on before this Court.

6. As noted above, the concerned Returning Officer is examined as a witness, his evidence is on record at Exh. 99 and the recording of his evidence was concluded on the last date of hearing i.e. 15.03.2019. It is now, that it has come on record, through the evidence of the Returning Officer himself that, many instructions of the Election Commission of India, including some of the mandatory instructions (at least on seven counts) were violated by the Returning Officer, on the



day of counting of votes, of the Election in question. The Returning Officer has also deposed before this Court that, before the declaration of the result, the Observer had certified vide Exh.112 that - after having satisfied herself about the fairness of counting of votes and complete accuracy of compilation of result in Form No.20, she had authorized the Returning Officer of 58-Dholka Assembly Constituency to declare the result.

7. The following (Paras 8 to 13) is the comparison of :-

(i) the standing instructions of the Election Commission of India as contained in the booklet called - 'Handbook for the Returning Officers - 2014', which are in public domain (website of the Election Commission of India) and which are on record of this petition at Exh.101,

vis-a-vis

(ii) the actual process undertaken by the Returning Officer on the day of counting of votes of the Election in question, as per the evidence of the Returning Officer himself, vide Exh.99.

8. REGARDING MANDATORY REVERIFICATION AND MANDATORY RECOUNT OF POSTAL BALLOTS

8.1 The instruction of the Election Commission of India, as contained in Para : 15.15.5.1 of the said Handbook Exh. 101, regarding mandatory re-verification of Postal Ballots reads as

under.

'In case the victory margin is less than total number of postal ballots received then there should be a **mandatory re-verification** of all postal ballots. In the presence of Observer and the RO all the postal ballots rejected as invalid as well as the postal votes counted in favour of each and every candidate shall once again be verified and tallied. The Observer and the RO shall record the findings of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result. The entire proceeding should be videographed without compromising the secrecy of ballot and the video-cassette / CD should be sealed in a separate envelope for future reference.'

8.2 The instruction of the Election Commission of India, as contained in Para : 15.30.9 of the said Handbook Exh. 101, regarding mandatory recount of Postal Ballots reads as under.

'The Commission has decided that where the result of an election is going to be decided by difference of postal ballot received by the first two candidates, then there shall be **mandatory and comprehensive recount** of postal ballot papers, even though no candidate ask for it.'

8.3 Relevant part of the deposition of the Returning Officer, with regard to the compliance of the above quoted instructions of the Election Commission of India, i.e. with regard to (i) mandatory re-verification of Postal Ballots and (ii) mandatory

and comprehensive recount of Postal Ballot papers, reads as under.

“276. Question : What was the victory margin of the returned candidate (respondent no.2) over the petitioner ?

Ans : 327 votes.

277. Question : You have deposed earlier that, total postal ballots received by you were 1356. Total postal ballots rejected by you were 429. Thus the victory margin of the returned candidate over the petitioner was less than total postal ballots received. In this situation, which of the instructions of the Election Commission of India would come into play ?

Ans. : In this situation, the instructions contained in Paras : 15.30.9 and 15.15.5.1 in the Hand Book (Exh.101) would come into play.

278. Question : Whether you had done the re-counting of postal ballots which is mandatory as per the above referred instructions (para : 15.30.9) ?

Ans. : No. I had not done that re-counting.

279. Question : Whether you had done the re-verification of postal ballots which is mandatory as per the above referred instructions (para :

15.15.5.1) ?

Ans. : No. I had not done that re-verification either.”

**9. REGARDING TIMING OF COMMENCEMENT OF COUNTING OF VOTES FOR THE PENULTIMATE ROUND OF EVMs.**

9.1 The instruction of the Election Commission of India, as contained in Para : 15.16.2 of the said Handbook Exh. 101, regarding timing of commencement of counting of votes for the penultimate round (second last round) of EVMs, reads as under.

'After 30 minutes of the commencement of postal ballot counting, the EVM counting can start. The EVMs can be brought under escort (agents can accompany) from the strong room to the counting hall even if the postal ballot counting is still going on. However, the penultimate round of EVM counting shall not commence unless the postal ballot counting is over.'

9.2 Relevant part of the deposition of the Returning Officer with regard to the compliance of the above quoted instructions of the Election Commission of India reads as under.

“282. Question : When the EVMs for the 2nd last round (penultimate round) were brought out of the strong room and were taken to the counting hall ?

Ans. : At 11:17:00 hours onwards.

283. Question : When the EVMs for 2nd last round were being brought in the counting hall, at that time, was the counting of postal ballot over ?

Ans. : No. That process was not over.

284. Question : What was the stage at Table No.15 when the EVMs for the 2nd last round were being brought in the counting hall ?

Ans. : At the request of the witness, CCTV footage is shown to him of VM626 - On RO table - time 11:07:52 to 11:17:58. On playing the said footage, the witness states that :- all the trays of the candidates are empty and even the distribution of the valid postal ballots candidate-wise had not started at that time."

## 10. REGARDING PROHIBITION OF USE OF MOBILE PHONE IN THE COUNTING HALL

10.1 The instructions of the Election Commission of India, as contained in Paras : 15.6.3, 15.6.4 and 15.14.1.7 of the said Handbook Exh. 101, regarding prohibition of use of mobile phone in the counting hall, read as under.

'15.6.3 Media centres have to be set up at each Counting Centre. As far as possible, a separate room of adequate size should be set apart for these centres and reasonable facilities like telephone, fax, data communication network etc have to be

provided. Each returning Officer is required to exclusively deploy one senior officer to be in charge of the Media Centre, preferably from the Public Relations Department. It is important that adequate number of officers/officials are available to assist the officer in charge of the Media Centre at each counting centre so that they can escort the media groups in small manageable numbers to visit counting halls from time to time. Such visits are to be of short duration only. All such visits will be escorted visits conducted by officers identified and earmarked for this purpose in advance. In the media room, adequate arrangements shall be made to keep the mobile phones safely because the mobile phones shall not be allowed to be taken inside the counting halls. Use of mobile phones and other communication equipment shall be allowed from the media centre. Mobile phones shall not be used from anywhere else within the campus.

15.6.4 Since nobody (not even the candidate or RO/ARO etc) except the observer shall be allowed to carry a mobile phone inside the counting hall, the DEOs and ROs will also arrange another room for the candidates, their agents etc to make use of their mobile phones in case of any need. Public Communication Room should also provide for a senior officer and arrangements for safe-keeping of the mobiles etc of the candidates and their agents/representatives.'

'15.14.1.7 Mobile phones are not to be allowed inside the counting centre. Only Commission's Observer's are allowed to carry mobile phone.'

10.2 Relevant part of the deposition of the Returning Officer with regard to the compliance of the above quoted instructions of the Election Commission of India reads as under.

'298. Question : The witness is shown the CCTV footages VM239 - RO table - Timings -

08:48:22 to 08:48:36

11:00:23 to 11:00:59

11:01:58 to 11:02:28

12:13:18 to 12:13:37

12:44:15 to 12:45:21

12:47:08 to 12:48:47

13:09:10 to 13:10:20

Can you explain what do you see ?

Ans. : In those footages, I see talking on my mobile phone.

299. Question : Can you recollect whom did you call or who called you at that time ?

Ans. : Those were official calls and may be one or two calls could be personal calls as well.'

## 11. REGARDING FORM 20 (FINAL RESULT SHEET)

11.1 The instruction of the Election Commission of India, as contained in Para : 15.15.3.6 of the said Handbook Exh. 101, regarding preparation of Final Result Sheet (Form 20), reads as under.

'The valid votes should then be counted and each candidate credited with the votes given to him. The total number of postal votes received by each candidate should then be calculated, entered in the Result Sheet in Form 20 in the appropriate place and announced by you aloud for the information of the candidates.'

11.2 Relevant part of the deposition of the Returning Officer with regard to the compliance of the above quoted instructions of the Election Commission of India, reads as under.

'287. Question : Before announcing the figures of postal ballots, at 12:24:00 hours, as stated by you above, did you enter that figure in Form No.20 ?

Ans. : I do not remember at this stage.

288. Question : What is the requirement in this regard, as per the instructions of the Election Commission of India ?

Ans. : From the Hand Book (Exh.101), I say that Para : 15.15.3.6 would come in play at that stage.



289. Question : When did you declare the final result?

Ans. : At 13:16:00 hours.

290. Question : Before declaring the final result, whether all figures were filled in - in Form No.20 ?

Ans. : Yes, that was done.

291. Question : When you say that all the figures were filled in - in Form No.20 before declaring the final result, it also included the figures of postal ballots ?

Ans. : Yes.

292. Question : When you entered the figures of postal ballots received by each candidate in Form No.20, before declaring the final result at 13:16:00 hours, as stated by you above, did you enter the same figure of postal ballots which you had announced at 12:24:00 hours ?

Ans. : No, it is not the same figure. There is difference in the figures of postal ballots as entered in Form No.20 and what was announced by me at 12:24:00 hours.

At this stage, the witness requested that he be

permitted to give some explanation in this regard.

On being permitted to do so, he states that :-

As it is evident even from the CCTV footage which is played in the Court in this regard today, even I had asked for the said figure from somebody else and subsequently, when it came to my notice that there is difference in that regard, I entered correct figures in Form No.20. I further say that, the figures which I had announced - what each candidate has got and what I entered in Form No.20, is the same in both the cases."

## 12. SATISFACTION TO BE RECORDED BY THE OBSERVER BEFORE AUTHORIZING THE DECLARATION OF THE FINAL RESULT

12.1 The instruction of the Election Commission of India, as contained in Para : 16.2.2 of the said Handbook Exh. 101, regarding satisfaction to be recorded by the Observer before authorizing the declaration of the final result by the Returning Officer, reads as under.

'No Returning Officer shall declare the result without receiving the authorization in the format as detailed above from the Observer. It shall be the personal responsibility of the Observer and Returning Officer to ensure fairness of counting of votes and accurate compilation of result.'

12.2 Relevant part of the deposition of the Returning Officer

with regard to compliance of the above quoted instruction of the Election Commission of India reads as under.

“273. Question : Whether you had got authorisation from the Observer before the declaration of the final result ?

Ans. : Yes. The same is on record at Annexure - R-1 to the written statement which I had filed earlier in this petition, which is on record as Exh.10. The said document (R-1 of Exh.10) is given Exh.No.112.”

12.3 The said document Exh.112, which is the certificate given by the Observer, regarding satisfaction recorded by her before authorizing the declaration of the final result by the Returning Officer, reads as under :-

**“DECLARATION OF RESULT**

Mrs. Vinita Bohra (IAS), Observer code (G22074) For 58-Dholka Assembly Constituency / Assembly segment of 17 - Kheda Parliamentary Constituency, after having satisfied myself about the fairness of counting of votes and complete accuracy of compilation of result in Form No.20 hereby authorize the Returning Officer of 58-Dholka Assembly Constituency to declare the result.

Sd/-

Name of the observer - Mrs. Vinita Bohra  
Code of the observer - G22074  
Assembly Constituency No. & Name: 58-Dholka”

### 13. VIDEO-GRAPHY OF THE COUNTING PROCESS

13.1 The instruction of the Election Commission of India, as contained in Para : 15.14.1.9 of the said Handbook Exh. 101, regarding video-graphy of the Counting process, reads as under.

'A CD containing the record of complete video-graphy of counting process should be given by the Returning Officer to all candidates or their election agents free of cost after the counting process is over.'

13.2 Relevant part of the deposition of the Returning Officer with regard to compliance of the above quoted instruction of the Election Commission of India reads as under.

“119. Question : By Exh.85, you declined to give DVD and thereby you have breached one more instruction of the Election Commission of India - What do you say ?

Ans. : The video-graphy inside the counting hall was done by the agency appointed by the District Election Officer, Ahmedabad and as the Returning Officer, I was not having the DVD at the time when the application was made and therefore, the same was not given.

121. Question : To how many candidates, did you give the said DVD ?

Ans. : Not to even one.”

14.1 On conjoint consideration of :-

- (i) the relevant facts,
- (ii) the Issues being tried in this petition, (as quoted above in para : 4),
- (iii) the comparison of :-

(a) the standing instructions of the Election Commission of India as contained in the booklet called - 'Handbook for the Returning Officers - 2014', which are in public domain (website of the Election Commission of India) and which are on record of this petition at Exh.101,

*vis-a-vis*

(b) the actual process undertaken by the Returning Officer on the day of counting of votes of the Election in question, as per the evidence of the Returning Officer himself, vide Exh.99,

as quoted in paras : 8 to 13 above,

(iv) the certificate given by the Observer (Exh. 112) before declaration of the result of the Election in question (as quoted in Para:12.3 above), and

(v) the mandate of Section 99 of the Representation of the People Act, 1951,

it would be necessary to give opportunity to both the concerned officers i.e. the Returning

Officer and the Observer, to put their case before this Court. For this purpose, they need to be joined as party respondents.

14.2 It would also be just and proper to put the facts noted in this Order to the notice of the Election Commission of India. It is noted that, what is recorded above is neither the opinion of the Court nor this Court has arrived at any judgment on any issue, however the facts noted above are so glaring that, this Court has thought it prudent to put the above noted facts to the notice of the Election Commission of India, so that it can consider and look into it and take appropriate corrective / preventive measures, if it so desires. For this purpose, the Election Commission of India also needs to be joined as party respondent. While joining the Election Commission of India as party respondent in this petition, this Court is conscious of the fact that the Election Commission of India can not be a contesting party, so far the Election in question is concerned. It is for the petitioner to prove his case and it is for the returned candidate to defend his Election. However, as noted above, the facts recorded above are so glaring that this Court has thought it prudent to put it to the notice of the Election Commission of India at this stage itself, so that it can consider and look into it, and take appropriate corrective / preventive measures now, if it so desires. For this limited purpose, the Election Commission of India needs to be and is being joined as party respondent.

14.3 It is noted that, while joining the Returning Officer (in his personal capacity) and the Election Commission of India as party respondents, this Court is conscious of the fact that, both of them were already party respondents in this petition as

respondents No.13 and 14 respectively, however both of them were deleted as party respondents, at their request, on the applications being Election Application No.11 of 2018 and Election Application No.41 of 2018. Reference in this regard is made to :- (i) the order dated 27.11.2018 recorded on Election Application No.11 of 2018, and (ii) the orders dated 19.12.2018 and 09.01.2019 recorded on Election Application No.41 of 2018. However, in view of the deposition of the Returning Officer, which concluded on the last day of the proceedings i.e. 15.03.2019, the necessity of joining them as party respondents has cropped up and therefore they are being joined as party respondents, at this stage, for the reasons recorded in paras : 14.1 and 14.2 above.

14.4 Since the Election Commission of India and both the officers, who are being joined as party respondents, may be busy with the Election process at present, in the event any request is made by or on behalf of any of them for adjournment on the next date of hearing, the Court may consider the same for appropriate accommodation.

15.1 In view of above, the following order is passed.

15.2 The following persons / authority are ordered to be joined as party respondent Nos. 13 to 15 in this petition.

- (1) Mr. Dhaval Jani, G.A.S.  
Deputy Collector at Dholka, District : Ahmedabad  
(the Returning Officer of  
'58 Dholka Assembly Constituency')

as Respondent No. 13

- (2) The Election Commission Of India  
Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road, New Delhi - 110001.

as Respondent No. 14

- (3) Mrs. Vinita Bohra , I.A.S.  
(Notice to be served through  
The Election Commission of India)  
Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road, New Delhi - 110001.

as Respondent No. 15

15.3 Issue notice to the newly added respondent Nos.13 to 15 returnable on 16.04.2019, with the clarification that, since all the newly added respondents may be busy with the Election process at present, in the event any request is made by or on behalf of any of them, for adjournment on the next date of hearing, the Court may consider the same for appropriate accommodation.

Over and above normal mode of service, Direct service is permitted. It would be open for the petitioner to serve the newly added respondents No.13 to 15, through registered Post.

**(PARESH UPADHYAY, J)**

M.H. DAVE/1